



एमएसपी की लीगल गारंटी

नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में विपक्षी दलों के भारी विरोध को देखते हुए भूमि सुधार पर अध्यादेश वापस लिया था। तब एक सवाल यह भी उठा था कि इससे

आर्थिक सुधारों की प्रगति पर बुरा असर पड़ेगा।

मर्नाज शाह।।

केंद्र के तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बाद भी किसान आंदोलन के खत्म होने की सूत्र नहीं दिख रही। इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि वह सरकार से लंबित मांगों पर बातचीत शुरू करने की अपील करेगा। वह सभी फसलों की खरीदारी के लिए खासतौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की लीगल गारंटी, किसानों पर दर्ज एफआईआर खत्म करने, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 वापस लेने की भी मांग कर रहा है। आंदोलन के दौरान जिन 670 किसानों की मृत्यु हुई, उनके लिए मोर्चा ने मुआवजे की भी मांग की है। सरकार एमएसपी पर एक कमिटी बनाने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन

लगतान नहीं कि यह मसला जल्द सुलझेगा। किसान संगठनों का कहना है कि एमएसपी पर लीगल गारंटी मिलने पर वह न्यूनतम कीमत बन जाएगी। तब सरकार के साथ निजी क्षेत्र को भी खरीदारी के लिए उस न्यूनतम मूल्य का भुगतान करना होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। इसे लागू करने में एक दिक्कत तो यह है कि न्यूनतम कीमत तय करने के साथ खरीदे जाने वाली फसल की गुणवत्ता का मानक भी तय करना होगा। अगर ऐसा हुआ तो इस मानक से नीचे अनाज के होने पर एमएसपी नहीं मिलेगी।

दूसरी बात यह है कि अभी यों तो 23 फसलों से एमएसपी का हर साल ऐलान होता है, लेकिन उनमें से खरीदारी पांच-छह फसलों की ही होती है। इसका फायदा भी

खासतौर पर पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे राज्यों के 10-12 प्रतिशत किसानों को मिलता है। इसलिए ज्यादातर किसानों को इससे कम दाम पर व्यापारियों को अनाज बेचना पड़ता है। इस मुश्किल को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश, केरल और हरियाणा जैसे राज्यों ने कुछ फसलों के लिए भावांतर योजना लागू की थी। इसमें वे इन फसलों के लिए एक कीमत तय करते थे। किसान अगर उस कीमत से कम पर फसल बेचने को मजबूर होते तो उस अंतर की भरपाई राज्य करते। इन योजनाओं से राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ता है, इसलिए लंबे वक्त तक उन्हें नहीं चलाया जा सकता। एमएसपी की लीगल गारंटी से खाद्यान्नों

की महंगाई भी बढ़ सकती है, जिससे शहरी मध्यवर्ग नाराज हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक भी इससे खुश नहीं होगा, जिस पर महंगाई दर को नियंत्रित रखने की जिम्मेदारी है। इसलिए इसका मौद्रिक नीति पर भी असर पड़ सकता है। यह भी ध्यान रखना होगा कि कृषि राज्य का विषय है। इसलिए इस मुद्दे पर उनके साथ भी विचार-विमर्श करना होगा। इस पूरे मामले में सभी पक्षों के हितों के बीच संतुलन साधने का काम एमएसपी कमिटी को करना होगा। उसे किसानों की आमदनी दोगुनी करने के सरकार के वादे, फसल की कम कीमत मिलने से किसानों की आमदनी घटने की शिकायत, एमएसपी व्यवस्था का लाभ बहुत कम किसानों को मिलने और कृषि उपज का निर्यात बढ़ाने जैसी जरूरतों के बीच तालमेल बिठाना होगा।

स्वर्ग पर आक्रमण

अशोक वोहरा।
देवी को आया

देख स्वयं प्रहलाद भी सोचे कि इस समय भाग जाने में ही भलाई थी। परंतु इस तरह तो यह समस्या समाप्त होने से रही थी

धर्म-दर्शन



दू बार-बार सुख सुविधाओं से युक्त स्वर्ग को पाने के लिए दैत्य गण स्वर्ग पर आक्रमण करते थे। इंद्र को पराजित करते थे और फिर शक्ति के हाथों हार कर उन्हें स्वर्ग से भागना पड़ता था। आवश्यक था कि उनके लिए रहने का एक स्थायी जगह हो, जहां वे सभी भयमुक्त होकर सभी सुख सुविधाओं का उपभोग करते हुए रह सकें। यह निवास स्थान सिर्फ शक्ति उनके लिए मुहैया करा सकती थी क्योंकि इंद्र को तो वे लोग हराकर स्वर्ग पर कब्जा करने में सक्षम थे। इस विचार से विष्णु भक्त प्रहलाद देवी की स्तुति करते हुए बोले, "हे माता! दानव चाहे किसी भी रूप में हो आप की ही संतान है।"

संपादकीय

जमीन की चढ़ती कीमतें

देशभर के प्रॉपर्टी व्यवसायियों ने यहां सक्रियता बढ़ा दी है। अयोध्या और इसके इर्द-गिर्द अकल्पनीय ऊंचे दामों पर जमीन की खरीद-बिक्री भविष्य की दृष्टि से भयभीत करती है। राम मंदिर आंदोलन तक यहां संगठनों और मंचों की सक्रियता थी। आंदोलन के बाद सब कुछ जैसे खत्म हो गया। अब ऐसे संगठन या मंच की आवश्यकता है, जो यहां की समस्याओं के समाधान के लिए नागरिक और प्रशासन दोनों स्तरों पर पहल करे। जिस ढंग से यहां गाइड के नाम पर आगंतुकों को बरगलाया जाता है, वह महान विरासत वाली अयोध्या नगरी की छवि को विरूपित करता है। ट्रस्ट के लोग बताते हैं कि आगंतुकों की संख्या 30 तक सीमित करने का कोई तार्किक आधार नहीं। मंदिर के अंदर ट्रस्ट ने एक प्रतिनिधि रखा है ताकि कोई प्रमुख व्यक्ति आए तो वह कंट्रोल रूम को सूचित करे और उसकी इजाजत से उसे अंदर ले जाए। कई अवसर आए हैं जब यह आदेश नहीं मिला। दरअसल, अयोध्या प्रशासन का हर अधिकारी क्षेत्र के लिए वीआईपी की हैसियत रखता है। इन अधिकारियों की गाड़ियां सीधे राम मंदिर तक जाती हैं। परिवार सहित वे या उनके रिश्तेदार, परिचित दर्शन कर आराम से लौटते हैं। यह विषय ऐसा है, जिसकी नए सिरे से समीक्षा की जानी चाहिए। कौन वीआईपी है, कौन नहीं, इसका भी निष्कर्षण किया जाना आवश्यक है। साधु-संतों, प्रबुद्ध नागरिकों का कोई मंच हो तो ये सारी गड़बड़ियां ठीक की जा सकती हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की सरकार अपने निर्णयों और कदमों से यह प्रचारित करने की कोशिश करती रही है कि अयोध्या को भव्य स्वरूप देकर पुनर्वापसी कराना उनका एक प्रमुख अजेंडा है।

जमीनी हकीकत

अवधेश कुमार।।

अयोध्या इस समय केवल भारत नहीं, संपूर्ण विश्व के हिंदुओं के लिए धार्मिक-सांस्कृतिक दृष्टि से शायद सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र है। बीजेपी और संघ परिवार ने श्रीरामजन्मभूमि मंदिर को भारत के सांस्कृतिक पुनरुदभव के प्रतीक के रूप में महिमामंडित किया है। उच्चतम न्यायालय की ओर से श्रीराम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला दिए जाने के पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की सरकार अपने निर्णयों और कदमों से यह प्रचारित करने की कोशिश करती रही है कि अयोध्या को भव्य स्वरूप देकर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गरिमा की पुनर्वापसी कराना उनका एक प्रमुख अजेंडा है। फेजाबाद की जगह अयोध्या नामकरण, सरयू घाट का सुंदरीकरण, महाआरती, लाखों दीपों की माला से दीपावली का आयोजन आदि उसी का हिस्सा हैं।

हाल ही में अपने सप्ताह भर के अयोध्या प्रवास में मैंने निकट से जो कुछ देखा, उसके बाद यह निष्कर्ष देना कठिन है कि जिन कल्पनाओं की चर्चा है, क्या वे वाकई उसी रूप में धरातल पर साकार हो रही हैं। लेकिन इसमें दो राय नहीं कि काफी काम हुए हैं। अयोध्या जैसे घने और पुरानी शैली के मंदिर और मकानों वाले शहर को नया रूप देने में वैसे भी समय लगेगा। नए



अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण, सड़कों का चौड़ीकरण, घुमावदार गलियों और उनसे लगे मकानों के पुनर्निर्माण आदि में भी वक्त लगना है। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जिसे आसानी से किया जा सकता है। अयोध्या में रामायण काल से जुड़े सांस्कृतिक पुरातात्विक और धार्मिक महत्व के ज्यादातर स्थल उपेक्षित हैं। ये देखरेख के अभाव में वीभत्स चित्र उपस्थित करते हैं। उदाहरण के लिए, मणि पर्वत एक प्रसिद्ध स्थल है। आपको वहां पहुंचते ही धक्का लगेगा। वही पुरानी, जीर्ण-शीर्ण सीढ़ियां, जिन पर बुजुर्गों के लिए चलना कठिन। ऊपर आपको खतरे का आधा मिटा हुआ बोर्ड दिखेगा। मान्यता है कि अयोध्या के वैभव का स्रोत मणि पर्वत ही था।

यही स्थिति संपूर्ण अयोध्या और रामायण से जुड़े आसपास के ज्यादातर स्थलों की है। विद्या कुंड, जहां सरस्वती के निवास की कल्पना है, चारों ओर गंदगी का ऐसा अंबार है कि आप खड़े नहीं हो सकते। यहां से थोड़ी दूरी पर भरत तपस्या स्थली और राम-भरत मिलाप के केंद्र नंदीग्राम की दुर्दशा देख आंखों में आंसू आ जाते हैं। भरतकुंड में इतनी गंदगी है कि आप अंजलि में जल उठा कर आचमन तक नहीं कर सकते। सरयू घाट पहले से काफी बेहतर हुआ है। महाआरती ठीक तरीके से होती है। संपूर्ण विश्व के लोगों ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को अरबों रुपये मंदिर निर्माण के लिए दिया। लेकिन ट्रस्ट के लोग भी पुलिस के सामने कमजोर दिखाई पड़ते हैं। जन्मभूमि में आरती के लिए ट्रस्ट को 30 लोगों का पास बनाने की अनुमति है। पुलिस या प्रशासन के लोग बिना उनसे पास लिए भी, जितनी संख्या में चाहें लोगों को अंदर ले जा सकते हैं। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोगों का कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से उनकी गाड़ियां कहीं भी जाएं, लेकिन जब वे आरती में शामिल होने आते हैं तो वह ट्रस्ट के माध्यम से होना चाहिए। इस अनुरोध को वे सुनने को तैयार नहीं हैं। अंदर साफ दिखाई पड़ता है कि 150-200 लोग आरती के समय उपस्थित रहें तो कोई समस्या नहीं होगी। बैठने के लिए कुर्सियों की संख्या ही 80 के आसपास है।

अष्टयोग-5054						
	3	7	5			2
5	38		32	1	27	
	4		2	3	6	
3	32		32		33	
6		4	7		5	
	24		36	4	30	5
1			7		2	

अपना ब्लॉग

छोटा जलप्रपात नई पीढ़ी के लिए मनोरंजन

मोहन। सरयू से पंपों द्वारा पानी को निकालकर बनाया गया छोटा जलप्रपात नई पीढ़ी के लिए मनोरंजन और रोमांच का स्थान बन रहा है। कम पानी में तैरने और सेल्फी आदि के लिए यह एक बेहतर स्थान हो सकता है। लेकिन अभी भी देश और दुनिया भर से कर्मकांड के लिए आने वाले लोगों की सारी व्यवस्थाएं पहले जैसी हैं। कल्पना करिए, विदेशी पर्यटक पड़ितों की टूटी-फूटी, ईट-पत्थर लगी हुई चौकियां देखेंगे तो वह भारत के बारे में कैसी छवि लेकर जाएंगे! सरयू घाट पर कुछ सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी हो तो लगातार उन सीढ़ियों को पानी से धोया जा सकता है, जहां पूजन सामग्री लोगों के पैरों की गंदगी बनी रहती है। अयोध्या में सबको परेशान करने वाली एक और समस्या है सुरक्षा के नाम पर होने वाली पुलिस की अति। किसी भी तीर्थ या पर्यटन स्थल की छवि मुख्यतः आगंतुकों के साथ पुलिस प्रशासन और आम लोगों के व्यवहार पर निर्भर करती है।

